

अनुसूचित जनजातियों में पोषण के स्तर का भौगोलिक अध्ययन

(रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

Geographical Study of Nutritional Level Among Scheduled Tribes

(With Special Reference to Rewa District)

शोध-निर्देशक

शोधार्थी

डॉ. आर.के. शर्मा

शशिकांत कुमार पटेल

प्राचार्य

भूगोल विभाग

इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय न्यू रामनगर

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी

जिला-सतना (म.प्र.)

महाविद्यालय रीवा

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले की अनुसूचित जनजातियों — विशेषतः कोल, गोंड, बैगा एवं खैरवार जनजातियों में पोषण के स्तर का भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। रीवा जिले की भौगोलिक स्थिति, वन-आच्छादित क्षेत्र, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन एवं पारंपरिक जीवन-शैली जनजातीय समुदायों की पोषण स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। जिले की तहसीलों—रीवा, सिरमौर, सेमरिया, त्योंथर, मंगवां, जवा, में अनुसूचित जनजातीय बस्तियों का सर्वेक्षण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रोटीन, आयरन, विटामिन एवं कैलोरी की कमी प्रचलित है, जिसके परिणामस्वरूप बाल-कुपोषण, मातृ रुग्णता तथा सामान्य शारीरिक दुर्बलता की उच्च दर देखी गई है। भौगोलिक अलगाव, परिवहन सुविधाओं का अभाव एवं सरकारी पोषण कार्यक्रमों की सीमित पहुँच इन समस्याओं को और जटिल बनाती है। शोध के अंत में नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य शब्द (Keywords): अनुसूचित जनजाति, पोषण स्तर, भौगोलिक अध्ययन, रीवा जिला, कुपोषण, जनजातीय स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, मातृ पोषण, बाल पोषण, पोषण कार्यक्रम।

1. प्रस्तावना

भारत में अनुसूचित जनजातियाँ (Scheduled Tribes) देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत हैं, जो मुख्यतः वन एवं पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 1.53 करोड़ जनजातीय लोग निवास करते हैं। इनमें गोंड, कोल, बैगा, भील, सहरिया, खैरवार आदि प्रमुख जनजातियाँ हैं। रीवा जिला, जो मध्यप्रदेश के उत्तर-पूर्वी भाग में विन्ध्य पठार पर स्थित है, जनजातीय आबादी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

पोषण किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य, उत्पादकता एवं सर्वांगीण विकास का आधारभूत स्तम्भ है। परंतु अनुसूचित जनजातियों में पोषण की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बनी हुई है। NFHS-5 (2019-21) के आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि जनजातीय बच्चों में ठिगनापन (Stunting), दुबलापन (Wasting) एवं अल्पभार (Underweight) की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से पोषण के अध्ययन का विशेष महत्व यह है कि यह बताता है कि किस प्रकार किसी क्षेत्र की भूमि, जलवायु, वनस्पति, परिवहन, बाज़ार पहुँच एवं सामाजिक संरचना मिलकर वहाँ के निवासियों के भोजन व्यवहार और पोषण स्तर को निर्धारित करती है।

रीवा जिले में अनुसूचित जनजातियाँ मुख्यतः सिरमौर, त्योंथर, जावा एवं सेमरिया तहसीलों के वन-क्षेत्रों में निवास करती हैं। इन क्षेत्रों में सड़क, अस्पताल, उचित मूल्य की दुकानों एवं शैक्षणिक संस्थाओं की सीमित उपलब्धता पोषण की समस्या को गंभीर बनाती है। प्रस्तुत शोध पत्र इसी संदर्भ में रीवा जिले की जनजातियों के पोषण स्तर का भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

2. शोध पत्र के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

(1) रीवा जिले की अनुसूचित जनजातियों में पोषण के स्तर का भौगोलिक विश्लेषण करना।

(2) जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण के प्रमुख कारणों एवं भौगोलिक कारकों की पहचान करना।

(3) जनजातीय महिलाओं एवं बच्चों में पोषण की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(4) पोषण स्तर पर भौगोलिक स्थिति, वन-आच्छादन, परिवहन पहुँच एवं कृषि पद्धतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

(5) सरकारी पोषण कार्यक्रमों — जैसे मध्याह्न भोजन, पोषण अभियान, आँगनवाड़ी सेवाएँ — की प्रभावशीलता का आकलन करना।

(6) जनजातीय क्षेत्रों में पोषण सुधार हेतु नीतिगत सुझाव एवं व्यावहारिक उपाय प्रस्तुत करना।

3. शोध पत्र का महत्त्व

प्रस्तुत शोध पत्र निम्नलिखित दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है:

3.1 शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक महत्त्व

यह शोध भूगोल, स्वास्थ्य विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के अन्तर्विषयक (Interdisciplinary) समन्वय का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। जनजातीय पोषण के स्थानिक (Spatial) पैटर्न का विश्लेषण भौगोलिक शोध को नई दिशा प्रदान करता है। यह शोध भविष्य के शोधार्थियों के लिए संदर्भ सामग्री का कार्य करेगा।

3.2 सामाजिक महत्त्व

अनुसूचित जनजातियाँ भारतीय संविधान के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त वर्ग हैं। उनके पोषण स्तर में सुधार का सीधा सम्बन्ध उनके जीवन-स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक समानता से है। यह शोध समाज को जनजातीय पोषण समस्याओं के प्रति जागरूक करता है।

3.3 नीतिगत महत्त्व

इस शोध के निष्कर्ष जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, जनजातीय कल्याण विभाग एवं योजना आयोग को साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण में सहायता प्रदान कर सकते हैं। पोषण कार्यक्रमों की भौगोलिक प्राथमिकता निर्धारण में यह अध्ययन उपयोगी होगा।

3.4 क्षेत्रीय महत्त्व

रीवा जिले पर केंद्रित यह अध्ययन बघेलखण्ड क्षेत्र की जनजातीय समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करता है। विन्ध्य पठार की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में जनजातीय पोषण के अध्ययन का यह पहला व्यापक प्रयास है।

4. शोध प्रविधि

4.1 शोध क्षेत्र

प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र रीवा जिला है, जो 24°18' से 25°12' उत्तरी अक्षांश तथा 81°2' से 82°18' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जिले का क्षेत्रफल लगभग 6,314 वर्ग कि.मी. है। जिले में नौ तहसीलें हैं – रीवा, सिरमौर, सेमरिया, त्योंथर, मंगवां, जावा, हनुमना, नईगढ़ी एवं मऊगंज।

4.2 शोध-प्रकार

यह शोध वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक (Descriptive and Analytical) प्रकृति का है। इसमें सामाजिक-भौगोलिक एवं स्वास्थ्य भूगोल की पद्धतियों का समन्वय किया गया है।

4.3 आँकड़ा-संकलन

प्राथमिक आँकड़े: अनुसूचित जनजातीय परिवारों में संरचित साक्षात्कार अनुसूची द्वारा सर्वेक्षण किया गया। जनजातीय महिलाओं, पुरुषों एवं किशोरियों से भोजन-आदतें, भोजन-विविधता, प्रतिदिन कैलोरी ग्रहण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की गई।

द्वितीयक आँकड़े: जनगणना 2011, NFHS-4 एवं NFHS-5, जिला स्वास्थ्य कार्यालय की रिपोर्ट, ICDS रिपोर्ट, NIN हैदराबाद के पोषण मानक, एवं राज्य जनजातीय कल्याण विभाग के दस्तावेजों का उपयोग किया गया।

4.4 प्रतिदर्श (Sample)

जिले की पाँच जनजातीय-बहुल तहसीलों सिरमौर, त्योंथर, जावा, सेमरिया एवं मंगवां से उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श विधि (Purposive Sampling) द्वारा कुल 300 जनजातीय परिवारों का चयन किया गया। प्रत्येक तहसील से 60 परिवार सम्मिलित किए गए।

4.5 विश्लेषण-विधि

आँकड़ों का विश्लेषण मानचित्रण, सांख्यिकीय तकनीकों (औसत, प्रतिशत, चि-वर्ग परीक्षण) एवं तुलनात्मक विधि से किया गया। GIS (Geographic Information System) की सहायता से पोषण के स्थानिक वितरण के मानचित्र तैयार किए गए।

5. अनुसूचित जनजातियों में पोषण के स्तर का भौगोलिक अध्ययन

5.1 रीवा जिले में अनुसूचित जनजातियाँ – एक परिचय

रीवा जिले में प्रमुख अनुसूचित जनजातियों में कोल, गोंड, बैगा, खैरवार एवं पनिका समुदाय सम्मिलित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार रीवा जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत लगभग 13 से 15 के बीच है। ये समुदाय मुख्यतः जिले के दक्षिणी एवं पूर्वी वन-क्षेत्रों – सिरमौर, त्योंथर एवं जावा की पहाड़ियों – में निवास करते हैं। इनकी जीविका वन-उत्पाद संग्रहण, पशुपालन एवं जीविकोपार्जी कृषि पर निर्भर करती है।

जनजाति	प्रमुख क्षेत्र (तहसील)	आजीविका का साधन	पोषण स्थिति
कोल	सिरमौर, त्योंथर, जावा	वन-उत्पाद, कृषि	मध्यम से निम्न
गोंड	सेमरिया, मंगवां	कृषि, पशुपालन	मध्यम

बैगा	त्योंथर (वन-क्षेत्र)	बेड़ा खेती, संग्रहण	अत्यंत निम्न
खैरवार	जावा, हनुमना	वन-उत्पाद, श्रम	निम्न
पनिका	रीवा, सेमरिया	बुनाई, श्रम	निम्न से मध्यम

स्रोत: जनगणना 2011, जिला जनजातीय कल्याण कार्यालय, रीवा एवं क्षेत्रीय सर्वेक्षण (शोधकर्ता)

5.2 भौगोलिक कारक एवं पोषण

रीवा जिले की भौगोलिक स्थिति जनजातीय पोषण को कई तरीकों से प्रभावित करती है। विन्ध्य पठार की ऊबड़-खाबड़ भूमि एवं घने वन जहाँ एक ओर जनजातियों को कंद-मूल, फल, पत्तेदार सब्जियाँ एवं शिकार जैसे पारंपरिक खाद्य स्रोत उपलब्ध कराते हैं, वहीं दूसरी ओर ये क्षेत्र परिवहन से कटे रहने के कारण बाज़ार, स्वास्थ्य सेवाओं एवं सरकारी वितरण प्रणाली से दूर रहते हैं।

जिले में वार्षिक औसत वर्षा लगभग 1000-1200 मिमी है, जो खरीफ फसलों – धान, ज्वार, कोदो-कुटकी – के लिए अनुकूल है। परंतु वर्षा की अनिश्चितता एवं सिंचाई सुविधाओं का अभाव खाद्य-उत्पादन को अनियमित बनाता है। सूखे के वर्षों में जनजातीय परिवारों में गंभीर खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है।

5.3 पोषण के स्तर का विश्लेषण

क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं एकत्रित आँकड़ों के आधार पर जनजातीय समुदायों में पोषण की निम्नलिखित स्थिति पाई गई:

पोषण संकेतक	जनजातीय क्षेत्र (रीवा)	मध्यप्रदेश औसत	राष्ट्रीय औसत (NFHS-5)
5 वर्ष से कम ठिगने बच्चे (%)	48.2%	42.0%	35.5%
5 वर्ष से कम दुबले बच्चे (%)	31.6%	25.8%	19.3%
5 वर्ष से कम अल्पभार बच्चे (%)	52.4%	42.8%	32.1%

एनीमिया (महिलाएँ) (%)	68.5%	54.6%	57.0%
प्रतिदिन कैलोरी ग्रहण (Kcal)	1480	1820	2100 (मानक)
प्रोटीन ग्रहण (ग्राम/दिन)	28	38	55 (मानक)

स्रोत: NFHS-5 (2019-21), क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं जिला स्वास्थ्य कार्यालय रीवा

5.4 भोजन-विविधता एवं आहार-संरचना

जनजातीय परिवारों में आहार-संरचना का विश्लेषण करने पर पाया गया कि 89% परिवार मुख्यतः अनाज (धान, गेहूँ, कोदो-कुटकी) पर निर्भर हैं। दाल एवं प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन सप्ताह में मात्र 2-3 बार होता है। हरी सब्जियाँ मौसमी वन-उत्पादों के रूप में उपलब्ध होती हैं, परंतु इनकी उपलब्धता केवल मानसून-पश्चात् के महीनों तक सीमित रहती है। दुग्ध एवं दुग्ध-उत्पादों का उपयोग अत्यंत सीमित (18% परिवारों में) पाया गया। अंडे एवं मांस का सेवन सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारणों से प्रतिबंधित है।

5.5 महिला एवं बाल पोषण

सर्वेक्षण में यह पाया गया कि जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं में आयरन की कमी (एनीमिया) की दर 68.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में अतिरिक्त पोषण की जानकारी एवं उपलब्धता दोनों की कमी पाई गई। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन एवं अल्पभार की उच्च दर कुपोषण की गंभीरता को दर्शाती है।

किशोरी बालिकाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। 15-18 वर्ष आयु वर्ग की 62% बालिकाओं का BMI (Body Mass Index) सामान्य से कम पाया गया। शीघ्र विवाह एवं प्रारंभिक गर्भावस्था की परंपरा किशोरी पोषण को और अधिक खराब करती है।

5.6 सरकारी पोषण कार्यक्रमों की स्थिति

रीवा जिले में ICDS (एकीकृत बाल विकास सेवाएँ) के अंतर्गत आँगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि जनजातीय बस्तियों में स्थित आँगनवाड़ी केंद्रों तक पहुँच सुगम नहीं है। दुर्गम क्षेत्रों में 35% परिवार नियमित रूप से आँगनवाड़ी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते। पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan) के तहत 2018 से जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, परंतु जनजातीय क्षेत्रों में इसकी प्रभावशीलता सीमित है।

कार्यक्रम	लाभार्थी प्रतिशत (जनजातीय)	प्रमुख समस्याएँ
ICDS / आँगनवाड़ी	65%	दूरी, जागरूकता की कमी
मध्याह्न भोजन	72%	अनुपस्थिति, गुणवत्ता
PDS (राशन)	78%	अनियमित आपूर्ति
पोषण अभियान	48%	सीमित पहुँच
जननी सुरक्षा योजना	55%	संस्थागत प्रसव की कमी

स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, रीवा

5.7 भौगोलिक विभिन्नता – तहसीलवार विश्लेषण

रीवा जिले की विभिन्न तहसीलों में जनजातीय पोषण स्तर में उल्लेखनीय भिन्नता पाई गई। त्योंथर तहसील, जो अत्यंत दुर्गम वनाच्छादित क्षेत्र है, में कुपोषण की दर सर्वाधिक (56%) पाई गई। इसके विपरीत, रीवा तहसील के जनजातीय परिवारों में बाजार एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुँच के कारण स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर (38%) पाई गई। सिरमौर एवं जावा की तहसीलें मध्यवर्ती स्थिति में हैं।

तहसील	जनजातीय परिवार (सर्वेक्षण)	कुपोषण दर (5 वर्ष से कम)	एनीमिया दर (महिला)
त्योथर	60	56.3%	74.2%
सिरमौर	60	51.8%	69.5%
जावा	60	49.2%	67.8%
सेमरिया	60	43.6%	65.1%
मंगवां	60	38.4%	63.0%
औसत	300	47.9%	67.9%

स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण, 2023-24

5.8 कुपोषण के प्रमुख कारण

क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं साक्ष्यात्मक आँकड़ों के आधार पर रीवा जिले की अनुसूचित जनजातियों में कुपोषण के निम्नलिखित प्रमुख कारण पाए गए। आर्थिक कारणों में निर्धनता, अनियमित एवं अपर्याप्त आजीविका, वन-अधिकारों की सीमित मान्यता एवं ऋण-चक्र प्रमुख हैं। भौगोलिक कारणों में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, खराब सड़क संपर्क, बाज़ार से दूरी एवं स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्त पहुँच उल्लेखनीय है। सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों में भोजन-वर्जनाएँ, अंधविश्वास, महिलाओं की निर्णय-लेने में सीमित भागीदारी, शैक्षिक पिछड़ापन एवं परिवार नियोजन की कमी शामिल हैं। कृषि सम्बन्धी कारणों में एकफसली कृषि, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एवं बीज-खाद की सीमित उपलब्धता महत्वपूर्ण हैं।

6. निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि रीवा जिले की अनुसूचित जनजातियों में पोषण की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। कुपोषण की उच्च दर, विशेष रूप से बच्चों एवं महिलाओं में, भौगोलिक अलगाव, आर्थिक पिछड़ापन एवं सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों का संयुक्त परिणाम है। भौगोलिक विश्लेषण स्पष्ट करता है कि त्योंथर एवं सिरमौर जैसी दुर्गम तहसीलों में स्थिति सर्वाधिक गंभीर है।

स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित किए जाते हैं। पहला, जनजातीय दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य एवं पोषण इकाइयाँ स्थापित की जाएँ। दूसरा, आँगनवाड़ी केंद्रों को जनजातीय बस्तियों के निकट स्थानांतरित किया जाए तथा उन्हें पर्याप्त संसाधनों से सुसज्जित किया जाए। तीसरा, जनजातीय महिलाओं को स्थानीय भाषा में पोषण शिक्षा प्रदान की जाए। चौथा, कोदो-कुटकी, रागी जैसी पोषण-समृद्ध पारंपरिक फसलों को प्रोत्साहित किया जाए। पाँचवाँ, वन-अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से जनजातियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। छठा, PDS प्रणाली में दाल, तेल एवं पोषक खाद्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाए।

संदर्भ (References)

1. अग्रवाल, ए.के. एवं मिश्रा, एस. (2018). मध्यप्रदेश में जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण। भारतीय सामाजिक विज्ञान समीक्षा, 12(3), 45-62।
2. कुमार, आर. एवं वर्मा, के. (2020). अनुसूचित जनजातियों में कुपोषण की समस्या: एक भौगोलिक विश्लेषण। भूगोल पत्रिका, 28(2), 112-128।
3. जनगणना भारत (2011). मध्यप्रदेश जनगणना प्रतिवेदन। नई दिल्ली: भारतीय जनगणना महानिदेशक।
4. तिवारी, एस. एवं सिंह, प्र. (2019). बघेलखण्ड की जनजातियाँ: सामाजिक-आर्थिक स्थिति। विन्ध्य शोध-पत्रिका, 6(1), 23-40।
5. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) (2021). मध्यप्रदेश तथ्य-पत्रक। मुम्बई: IIPS।
6. पाण्डेय, बी.एन. (2015). भारत में जनजातीय भूगोल। इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन।

7. भारत सरकार (2018). पोषण अभियान: राष्ट्रीय पोषण मिशन दिशा-निर्देश। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. मिश्रा, आर.के. (2017). रीवा जिले की जनजातियाँ: इतिहास, संस्कृति एवं विकास। रीवा: अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय।
9. यादव, डी. एवं त्रिपाठी, एन. (2022). विन्ध्य क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण। जर्नल ऑफ रूरल स्टडीज, 15(4), 78-95।
10. शर्मा, एम.एल. (2016). आदिवासी भारत की पोषण समस्याएँ। नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
11. Directorate of Tribal Welfare, MP (2022). Annual Report 2021-22. Bhopal: Government of Madhya Pradesh.
12. National Nutrition Monitoring Bureau, NIN (2012). Diet and Nutritional Status of Tribal Population. Hyderabad: ICMR.
13. Vijayaraghavan, K. & Brahmam, G.N.V. (2019). Nutrition Status in India's Scheduled Tribes. Indian Journal of Community Medicine, 44(1), 8-14.
14. WHO (2020). Malnutrition Fact Sheet. World Health Organization, Geneva.
